



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 434]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 1976/प्राश्विन 7, 1898

No. 434]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 1976/ASVINA 7, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September 1976

S.O.643(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 566(E), dated the 1st October, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that (a) the enactments, or portions thereof, as the case may be, specified in the Schedule of the said Order shall not apply to the industrial undertaking known as Amritsar Sugar Mills Co. Ltd., Amritsar (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) in so far as it relates to the factory known as Amritsar Oil Works, Amritsar (hereinafter referred to as the said factory), and (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions), to which the said industrial undertaking is a party in so far as they related to the said factory, or which may be applicable to it immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year commencing from the 1st October, 1975;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by another one year, commencing from the 1st October, 1976;

(1885)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby further extends the duration of the said Order upto 30th September, 1977.

[No. 4/3/74-C.U.C.]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

**उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)**

**आदेश**

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1976

**का० आ० 643 (अ).—**भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और सिविल आपूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 566 (ई), तारीख 1 अक्तूबर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन, अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा, 18 बख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित किया था कि (क) उक्त आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, अधिनियमितियां या उनके भाग, अमृतसर शुगर मिल्स क० लिमिटेड, अमृतसर नामक औद्योगिक उपक्रम को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है), जहां तक उसका सम्बन्ध अमृतसर आयल वर्क्स, अमृतसर नामक कारखाने से (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कारखाना कहा गया है) है, लागू नहीं होंगे और (ख) सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, जो प्रवृत्त हों (और जो उनसे भिन्न हों जिनका सम्बन्ध बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से हो), जिनमें उक्त औद्योगिक उपक्रम, वहां तक जहां तक उनका सम्बन्ध उक्त कारखाने से है, एक पक्षकार है, अथवा जो राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व उसे लागू हों, प्रवर्तन और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन उद्भूत या प्रोद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व, 1 अक्तूबर, 1975 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए लम्बित रहेंगे ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 1 अक्तूबर, 1976 से एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 बख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि को 30 सितम्बर, 1977 तक के लिए बढ़ाती है ।

[सं० 4/3/74-सी०यू०सी०]

अरुण कुमार घोष, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
निर्धनक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976